लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1915

11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्त्र क्षेत्र का आधुनिकीकरण

1915. श्री राजा राम सिंह:
श्री सुदामा प्रसाद:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वस्त्र क्षेत्र के विकास और आधुनिकीकरण के उद्देश्य से विभिन्न क्षेत्र-विशिष्ट योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) 7 मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान (पीएम मित्र) पार्क स्थापित करने के लिए कौन-कौन से स्थान चुने गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने रोजगार सृजन, निर्यात वृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद में योगदान पर इन पार्कों के प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई समिति गठित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पार्क स्थापित करने के लिए चुने गए प्रमुख हितधारकों का ब्यौरा क्या है और इस नीति को लागू करने के संबंध में उनके साथ किए गए परामर्श का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र मंत्री
(श्री गिरिराज सिंह)

(क): निर्यात सहित वस्त्र क्षेत्र की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए, सरकार एकीकृत वस्त्र पार्क (एसआईटीपी) योजना, एकीकृत प्रसंस्करण विकास योजना (आईपीडीएस), उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना, राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम), समर्थ - वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना एटीयूएफएस, सिल्क समग्र-2, राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) आदि सहित विभिन्न योजनाओं/पहलों को क्रियान्वित कर रही है।

(ख): सरकार ने वस्त्र उद्योग की संपूर्ण मूल्य-श्रृंखला के लिए एकीकृत बड़े पैमाने की और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधा विकसित करने के उद्देश्य से, वर्ष 2021-22 से वर्ष 2027-28 तक की अवधि के लिए 4,445 करोड़ रुपये के योजना परिव्यय से ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड साइटों में 7 (सात) पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और अपैरल (पीएम मित्र) पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। सरकार ने पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए 7 साइटों अर्थात् तमिलनाडु (विरुद्धनगर), तेलंगाना (वारंगल), गुजरात (नवसारी), कर्नाटक (कलबुर्गी), मध्य प्रदेश (धार), उत्तर प्रदेश (लखनऊ) और महाराष्ट्र (अमरावती) को अंतिम रूप दिया गया है।

(ग) और (घ): पीएम मित्र योजना को क्रियान्वित करने के लिए भारत सरकार और पीएम मित्र राज्यों के बीच समझौता ज्ञापनों के साथ-साथ संयुक्त उद्यम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सभी ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्कों में विशेष प्रयोजन तंत्र (एसपीवी) शामिल किए गए हैं, जिनमें राज्य सरकारों की एसपीवी में 51% हिस्सेदारी है और शेष 49% भारत सरकार के पास है।

एक बार पार्क के पूरा हो जाने पर यह अनुमान है कि प्रत्येक पीएम मित्र पार्क से लगभग 10,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित करेगा और लगभग 3 लाख (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

अब तक राज्यों, निवेशकों, संभावित पार्क डेवलपर्स सहित विभिन्न स्टेकहोल्डरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर लगभग 50 विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम और परामर्श किए जा चुके हैं।

***